भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 329
उत्तर देने की तारीख 18 दिसम्बर, 2024

इंटरनेट सुविधा की पहुंच

***329. डॉ. निशिकान्त दुबे:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषतः झारखंड सहित देश भर में, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट की सुलभता और किफ़ायत सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीति अपनाई है और यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त डिजिटल सुविधा के अंतर को पाटने और देश भर में इंटरनेट सुविधा के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की जा रही है; और
(ग) यदि हां, तो विशेषकर झारखंड राज्य में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"इंटरनेट सुविधा की पहुंच" के संबंध में दिनांक 18 दिसंबर, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 329 के भाग (क) से (ग) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में इंटरनेट की पहुँच वायरलेस मोबाइल और फिक्स्ड वायरलाइन ब्रॉडबैंड के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

सरकार ने मोबाइल कनेक्टिविटी और ऑप्टिकल फाइबर रोलआउट के माध्यम से भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इनके परिणामस्वरूप, अक्टूबर, 2024 तक:

- 783 जिलों में फैले 4जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) की संख्या 24,96,644 तक पहुंच गई है
- भारत में 5जी सेवाओं का दुनिया का सबसे तेज़ रोलआउट हुआ है जिसमें 779 जिलों में 4,62,084 बीटीएस संस्थापित किए गए हैं
- डेटा की लागत 269 रुपये प्रति जीबी (मार्च 2014 में) से घटकर 9.08 रुपये प्रति जीबी हो गई है
- मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड मार्च 2014 के 1.30 एमबीपीएस से बढ़कर 95.67 एमबीपीएस हो गई है
- प्रति उपभोक्ता औसत वायरलेस डेटा उपयोग बढ़कर 22.24 जीबी प्रति उपभोक्ता प्रति माह हो गया है

देश के 6,44,131 गांवों में से 6,15,836 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी है। झारखंड के कुल 32,370 गांवों में से 31,546 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) (पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)) अल्पसेवित ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की सार्वभौमिक सेवा प्रदान करने में सहायता के लिए अधिदेशित है। डीबीएन द्वारा वित्तपोषित विभिन्न स्कीमों जैसे भारतनेट और 4जी सेच्युरेशन परियोजनाओं के माध्यम से झारखंड सहित देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को ऑप्टिकल फाइबर और मोबाइल इंटरनेट से जोड़ा गया है। झारखंड की 4,416 ग्राम पंचायतों (जीपी) में से 4,390 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के माध्यम से भारतनेट परियोजना के तहत सेवा के लिए तैयार किया गया है।

सरकार ने अगस्त 2023 में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को भी मंज़ूरी दी है। यह कार्यक्रम रिंग टोपोलॉजी में 2.64 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर (ओएफ) कनेक्टिविटी द्वारा इंटरनेट की सुलभता प्रदान करता है और शेष गैर- ग्राम पंचायत गांवों (लगभग 3.8 लाख) को मांग के आधार पर ओएफ कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

*****